## 21

## अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

## संख्या 8/2018–राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(94)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/101.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंत:राज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर) की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने राज्य कर से छूट प्रदान करती है, जितना की वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है ।

सारणी

सारणा					
क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष,	माल का विवरण	दर		
	उप शीर्ष या				
	टैरिफ मद				
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	8703	1200 सी सी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मि मी या	9%		
		उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम			
		गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित मोटर			
		वाहन.			
		<b>स्पष्टीकरण-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश			
		मोटार वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम			
		(1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा			
2.	8703	1500 सी सी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मि मी की	9%		
		इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन.			
		<b>स्पष्टीकरण-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटरवाहनों का विनिर्देश			
		मोटार वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम			
		(1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा			
3.	8703	पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता	9%		
		1500 सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी			
		व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स			
		भी आते हों ।			
		<b>स्पष्टीकरण–</b> इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन			
		भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका			
		ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो ।			
4.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या	6%		
		3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न			

# स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

- ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यह़ास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहृास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और
- अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा ।

- यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम,
   2017, की धारा 2 की उपधारा (63) में परिभाषित इन पुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम,
   2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।
- 3. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

#### NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

### No. 08/2018-State Tax (Rate)

No. F. 3(94)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/101.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the state tax on intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are given in corresponding entry in column (2), from so much tax as specified in Schedule IV of Notification No. 1/2017–State Tax (Rate), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4), of the said Table, on the value that represent margin of the supplier, on supply of such goods.

S. No.	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	Old and used, petrol Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more. <b>Explanation</b> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%
2.	8703	Old and used, diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm <b>Explanation</b> For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	9%

Table

3	8703	<ul> <li>Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles.</li> <li>Explanation For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.</li> </ul>	9%
4.	87	All Old and used Vehicles other than those mentioned from S. No. 1 to S. No. 3	6%

Explanation - For the purposes of this notification, -

- (i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income-Tax Act,1961(43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored; and
- (ii) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored.

2. This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid, on such goods.

3. This notification shall come into force with effect from the 25th January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

## अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

## संख्या 9/2018–राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(95)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/102.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (एतश्मिन पश्चात जिसे ''उक्त अधिनियम'' से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व -1) की अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 28 नवम्बर, 2017 सं. फा. 03(63)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/771 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

''सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों''

- (ii) कॉलम 4 में, 'विज्ञान और अनुसंधान विभाग' शब्दों के स्थान पर 'विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में, "विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :-